

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 355/2009/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सेमकोर ग्लास लिमिटेड,
नया नोहरा, कोटा

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 2/ई.टी. /2006-07/माल पर प्रवेश कर में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 12(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2002-03 के लिये प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(4) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.3.2006 को पारित करते हुए राज्य के बाहर से प्रवेश कर योग्य अधिसूचित वस्तु LDO Lub. Oil, LPG, Propane Gas तथा Super LDO के आयात पर प्रवेश कर की देयता मानते हुए कर रुपये 29,44,119/- व घोषणा पत्र ETLA-3 व ETLA-5 विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये शास्ति रुपये 500/- का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय

31

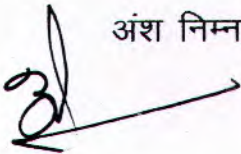
A

अधिकारी ने प्रवेश कर को यथावत रखा परन्तु खरीद मूल्य में से MODVAT की राशि को कम करते हुए तदनुरूप प्रवेश कर की गणना करने का निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
4. प्रस्तुत अपील में विवादित बिन्दु यह है कि राज्य के स्थानीय क्षेत्र में लाये जाने वाले माल पर चुकाई गई Excise Duty का जो MODVAT Credit विनिर्माण के स्तर पर Set off के रूप में उपलब्ध होता है क्या वह प्रवेश कर प्रयोजनार्थ 'माल के कर योग्य क्रय मूल्य' का भाग माना जायेगा अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 'कर योग्य क्रय मूल्य' वह सम्पूर्ण राशि है जो माल के राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय तक भुगतान/वहन की गयी है। प्रवेश कर अधिनियम में दी गयी परिभाषाओं के अन्तर्गत कर योग्य खरीद मूल्य की परिभाषा निम्न प्रकार है :-

"2(r) "taxable purchase value of the goods" shall mean the purchase price at which a dealer has purchased the goods inclusive of charges borne by him as cost of transportation, packing, forwarding and handling commission, insurance, taxes, duties and the like, or if such goods have not been purchased by him, the prevailing market price of such goods in the local area;"

5. उल्लेखनीय है कि The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 तथा The Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979 के अन्तर्गत 'Taxable Purchase Value of the Goods' की परिभाषाएं एक समान हैं तथा MODVAT की राशि माल के कर योग्य क्रय मूल्य का हिस्सा होगी अथवा नहीं, का यह बिन्दु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Karnataka v. Hansa Corporation** तथा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **Motor Industries Company Limited V/s State of Karnataka (C.R.P. No. 1550-1552/1996)** तथा **BPL Limited vs State of Karnataka And Anr. (2008) 11 VST 835 (Karn)** के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों में विस्तृत रूप से निर्णीत किया जा चुका है।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Karnataka v. Hansa Corporation** के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि प्रवेश कर राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के समय उसकी कीमत पर देय है। इस निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं:-



"...The taxing event is the entry of scheduled goods into a local area. The tax becomes payable on the entry of scheduled goods in a local area. Therefore, the price of the scheduled goods at the time of entry paid by the dealer who is the importer of goods within the scheduled area would be the ad valorem price on the basis of which tax would be computed. No subsequent rise or fall in price has any relevance to the computation of the tax."

7. इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **BPL Limited vs State of Karnataka And Anr. (2008) 11 VST 835 (Karn)** के प्रकरण में कर्नाटक प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत माल के कर योग्य क्रय मूल्य (Taxable Purchase Value of the Goods) की परिभाषा, जो कि राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम के समान ही है, की व्याख्या करते हुए इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि MODVAT प्रवेश कर के प्रयोजनार्थ माल की खरीद के लिये चुकाये गये मूल्य में से कमी के रूप में क्रियाशील नहीं है तथा यह केवल Excise Duty के भुगतान हेतु set off के रूप में कार्य करता है। इस निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

"14. For the purpose of entry tax, what is relevant is the value of goods when the goods enter the local area. The fact subsequent to such entry, the assessee received the goods in his factory and took MODVAT credit for the Excise duty paid on such goods, will not have the effect of reducing the value of the goods on entry into the local area."

"17. MODVAT credit does not operate as a "reduction" or "discount" in the purchase price paid to the supplier. MODVAT is only a procedure whereby the manufacturer utilises the credit for specific excise duty on inputs against duty payable on the final product. MODVAT credit taken on inputs is in the nature of set-off available against the payment of excise duty on the final product. Therefore, the decisions relating to "cost" for purposes of excise duty, have no relevance for determining the "value of goods" under Section 2(A)(8a) of the KTEG Act for purposes of entry tax. We therefore hold that for determining the value of goods for levy of entry tax, MODVAT credit availed by assessee on such goods cannot be deducted. The assessing officer was justified in rejecting the request for

31

A

deducting Rs. 57,65,64,884 in determining the taxable turnover."

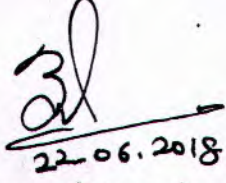
8. प्रत्यर्थी की ओर से अपने पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Collector of Central Excise, Pune v. Dai Ichi Karkaria Ltd. [1999] 7 SCC 448 का जो निर्णय उल्लिखित किया गया है वह सेन्ट्रल एक्साईज के तहत मूल्य के निर्धारण से सम्बन्धित है, जिसे प्रवेश कर के निर्धारण हेतु लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय को उल्लिखित करते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा Motor Industries Company Limited V/s State of Karnataka C.R.P. No. 1550-1552/1996 निर्णय दिनांक 29.09.1999 में यह स्पष्ट रूप से निर्णीत किया है कि उक्त निर्णय पिटीशनर को प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत माल के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं करता है। इस निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

"So far as the assessee is concerned, he has paid Rs. 100 to the seller as value of the goods. The subsequent benefit by way of MODVAT it would not be claimed at the time of entry of goods into the local area. The act of claiming the MODVAT is after the goods enter in the factory premises and not at the stage when the entry is in the local area. In these circumstances for the purpose of entry tax, the purchase value of goods is as specified in the bill including all other charges as mentioned in Clause (8a) of Section 2 thereof included. Therefore the above decision in Dai Ichi [1999] 7 SCC 448 cannot give any benefit to the assessee."

9. उक्त विवेचित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णीत किया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत चुकाई गई Excise Duty व उसके सम्बन्ध में निर्माता को Set off के रूप में प्राप्त होने वाले MODVAT/CENVAT को प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 'Taxable Purchase Value of the Goods' के निर्धारण में कम नहीं किया जा सकता है तथा स्थानीय क्षेत्र में व्यवसायी के स्थल तक वहनित किये गये समस्त खर्चे एवं कर आदि 'माल का कर योग्य क्रय मूल्य' का हिस्सा होंगे तथा इसी क्रय मूल्य पर नियमानुसार प्रवेश कर का आरोपण किया जायेगा। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा MODVAT की राशि को कम करते हुए प्रवेश कर की गणना हेतु निर्देश देते हुए जो प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।




10. उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा MODVAT के बिन्दु पर किया गया अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी की गणना को पुनर्स्थापित करते हुए आरोपित कर की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य